क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 312, बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

13 दिसंबर से 15 फरवरी तक ये ट्रेनें निरस्त, कई बदले हुए मार्ग से चलेंगी

लखनऊ। कोहरे के नाम पर रेलवे ने इस बार कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को गुरुवार से 15 फरवरी तक निरस्त कर दिया है। इसमें जनता एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, बरेली प्रयाग एक्सप्रेस, आगरा इंटरसिटी(Janata E&press, Shahid E&press, Bareli Prayag E&press, Agra Intercity,) और डबल डेकर सरीखीं ट्रेनें शामिल की हैं। रेलवे ने इस बार करीब 30 ट्रेनों को निरस्त किया है। जबकि, 25 ट्रेनों के फेरे घटा दिए हैं। इसके अतिरिक्त कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से भी चलाने का निर्णय लिया है।

15 फरवरी तक ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

14265-14266 जनता एक्सप्रेस
14307-14308 बरेली-प्रयाग एक्सप्रेस
14221-14222 फैजाबाद-कानपुर इंटरसिटी
14235-14236 वाराणसी-बरेली एक्सप्रेस
14523-24 हरिहर एक्सप्रेस
14673-14674 शहीद एक्सप्रेस
12179-12180 आगरा इंटरसिटी
12583-12584 लखनऊ जं.-आनंद विहार डबल डेकर एक्सप्रेस
11109-11110 लखनऊ जं.-झांसी इंटरसिटी
13257-13258 दानापुर-आनंद विहार जनसाधारण
14003-14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस
15209-15210 सहरसा-अमृतसर एक्सप्रेस
13119-13120 सियालदह-आनंद विहार एक्सप्रेस

इनके फेरों में आएगी कमी

- ट्रेन 13239-13240 पटना-कोटा एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन कम चलेगी। जबकि, ट्रेन 13237-13238 पटना-कोटा एक्सप्रेस सप्ताह में पूर्व की भांति तीन दिन चलेगी।
- ट्रेन 13307-13308 गंगा सतलज एक्सप्रेस और 15203-15204 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस का एक फेरा घटेगा।
- ट्रेन 12225 कैफ्यित एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार आजमगढ़ और 12226 कैफ्यित एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार दिल्ली से निरस्त रहेगी।
- ट्रेन 12331 हिमगिरी एक्सप्रेस हावड़ा से प्रत्येक मंगलवार और 12332 हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मूतवी से प्रत्येक गुरुवार नहीं चलेगी।
- ट्रेन 13005 पंजाब मेल हावड़ा से प्रत्येक सोमवार एवं 13006 पंजाब मेल अमृतसर से प्रत्येक गुरुवार नहीं चलेगी।
- ट्रेन 13151 सियालदह एक्सप्रेस कोलकाता से प्रत्येक बुधवार और 13152 सियालदह एक्सप्रेस जम्मूतवी से प्रत्येक शुक्रवार नहीं चलेगी।
- ट्रेन 13049 डुप्लीकेट पंजाब मेल हावड़ा से प्रत्येक मंगलवार और 13050 पंजाब मेल अमृतसर से प्रत्येक गुरुवार निरस्त रहेगी।
- 15705 चंपारन हमसफर एक्सप्रेस कटिहर से प्रत्येक गुरुवार एवं 15706 चंपारन हमसफर एक्सप्रेस दिल्ली से प्रत्येक शुक्रवार नहीं चलेगी।
- ट्रेन 11123-11124 बरौनी-ग्वालियर-ग्वालियर मेल सप्ताह में दो दिन, 12595-12596 हमसफर एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन नहीं चलेगी।

आंशिक निरस्त रहेगी इलाहाबाद-हरिद्वार

ट्रेन 14115-14116 इलाहाबाद-हरिद्वार एक्सप्रेस इलाहाबाद की जगह प्रयाग से चलेगी। जबकि, ट्रेन इलाहाबाद से प्रयाग के बीच निरस्त रहेगी।

बदले हुए मार्ग से चलेगी पटना-कोटा

पटना से कोटा के बीच चलने वाली ट्रेन 13237/38-13239/40 पटना-कोटा-पटना एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग कानपुर-टूंडला-आगरा-मथुरा-भरतपुर की जगह कानपुर के रास्ते फर्रुखाबाद-कासगंज-मथुरा-अछनेरा होकर भरतपुर होकर गुजरेगी।

कोच्चि में सोमवार को एक दीवार पेंटिंग के सामने से गुजरते लोग। कोच्चि में 12 दिसम्बर को समकालीन कला पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।

प्रयागराज महापौर अभिलाषा बोलीं, मुझे तो 'मी टू' के नाम से डर लगता है

प्रयागराज। महिलाओं के यौन शोषण को लेकर देशभर में जोर पकड़ चुके 'मी टू अभियान पर प्रयागराज(Prayagraj) नगर की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी (Mayor Abhilasha Gupta Nandi)ने सोमवार को कहा, मुझे तो 'मी टू (OMe TooO)के नाम से डर लगता है। सोमवार को यमुना पार नैनी में 'मी टू नाम से एक रेस्तरां का उद्घाटन करने आईं अभिलाषा ने कहा, कुछ लोग 'मी टू अभियान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई महिला किसी घटना के 10 साल बाद 'मी टू के तहत आरोप लगा रही है तो यह साहस तो उसमें घटना के समय भी रहा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उत्पीड़न की शिकार महिलाओं का सामने आना अच्छी बात है लेकिन इस अभियान के गलत इस्तेमाल से किसी व्यक्ति की जीवन भर की प्रतिष्ठा पल भर में मिट्टी में मिल जाती है।

रेस्तरां के मालिक शशांक सक्सेना ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह रेस्तरां खोलने का एक उद्देश्य होटल मैनेजमेंट के छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए मंच प्रदान करना भी है। सक्सेना मुट्ठीगंज में एक होटल प्रबंधन संस्थान भी चलाते हैं।

बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत अर्जी खारिज

लखनऊ। सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने उन्नाव रेपकांड (nnao Rape) मामले में निरुद्ध विधायक कुलदीप सिंह सेंगर(BJP MLA Kuldeep Sengar) की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बीते एक दिसंबर को सीबीआई की इस विशेष अदालत से शशि की भी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। बीते 11 जुलाई को सीबीआई ने नाबालिग से रेप के इस मामले में इन दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने सेंगर व शशि को आईपीसी की धारा 120बी सपठित धारा 363, 366, 376(1) व 506 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कुल 49 गवाह व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं।

आगरा, मथुरा, प्रयागराज और वाराणसी में हेलीकॉप्टर सेवा जल्द

लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा(Helicopter service) के लिए चार जिलों में एयर स्ट्रिप के लिए नि:शुल्क भूमि हस्तांतरण व खरीदने संबंधी फैसले मंगलवार को लिए। इसमें आगरा, मथुरा, प्रयागराज व वाराणसी (ir Strip in Agra, Mathura, Prayagraj and Varanasi) में एयर स्ट्रिप बनाई जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक(Cabinet meeting) में ये फैसला किया गया। आगरा में एयर स्ट्रिप के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के करीब यूपी एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 2.2656 हेक्टेयर भूमि निशुल्क ली जाएगी। वहीं इसके बगल में आगरा विकास प्राधिकरण की .4290 हेक्टेयर व निजी स्वामित्व की .0267 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इनका अनुमानित मूल्य क्रमश: 94 लाख 33 हजार 600 रुपये और 5 लाख 87 हजार 400 रुपये हैं। मथुरा में गोर्वधन में हेलीपोर्ट बनेगा। यहां पैंठा में उपलब्ध पांच हेक्टेयर जमीन राजस्व विभाग से पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा वाराणसी के डोमरी गांव में उपलब्ध 3.159 हेक्टेयर जमीन का हस्तांतरण निशुल्क होगा। प्रयागराज में ग्रामसराय मौज में .228 हेक्टेयर जमीन को स्थायी हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए आरक्षित कर पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसमें आगे निर्णय लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इस योजना के लिए 2473.25 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं और इसके लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

उरई में दरोगा ने जीआरपी बैरक में खुद को गोली से उड़ाया, हालत गंभीर

उरई। जीआरपी के दरोगा ने सोमवार को देर रात बैरक में सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। उसे उपचार के लिए नाजुक हालत में पहले कानपुर फिर लखनऊ ले जाया गया है। यहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जीआरपी के पुलिस अधीक्षक को घटना की वजह पारिवारिक बताई है ।

रेलवे पुलिस के स्थानीय थाने में तैनात औरैया निवासी उप निरीक्षक मोहित दुबे (28) ने देर रात बैरक के अंदर सर्विस रिवाल्वर से अपने को गोली मार ली। उसने इतनी सफाई से गोली मारी कि बगल में सो रहे सिपाही को भी पता नहीं चला।

इसी बीच पुष्पक एक्सप्रेस के कालपी पहुंचने पर ट्रेन की चेकिंग के लिए जीआर पी थानाध्यक्ष बृजमोहन सैनी मुस्तैद हुए तो उन्होने कहा कि मोहित को भी बुलवा लो। उनके आदेश पर सिपाही पवन शिवहरे मोहित को लेने जैसे ही बैरक में पहुंचा वहां खून से लथपथ पड़े दरोगा को देख कर उसके होश उड़ गए।

थानाध्यक्ष बृजमोहन सैनी फौरन मोहित को जिला अस्पताल की इमर्जेंसी में ले आए। बाद में झांसी से जीआरपी के पुलिस अधीक्षक प्रताप नारायण मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंच कर उसके बयान दर्ज किए।

मोहित ने बताया कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान था जिसके चलते यह कदम उठा बैठाया। उसे देखने वाले डाक्टर ने बताया कि उसने शराब भी पी रखी थी।

जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉ अरविंद चतुर्वेदी भी शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रुद्र कुमार सिंह के साथ अस्पताल में घायल दरोगा को देखने पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया था जिसके बाद पहले उसे कानपुर ले जाया गया,बाद में लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

यूपी के 40 लाख गरीब परिवारों को अब हर माह चीनी देगी सरकार

लखनऊ। राज्य सरकार अंत्योदय श्रेणी(Antyodaya category) में आने वाले करीब 40 लाख गरीब परिवारों को चीनी देगी। इस योजना में हर माह प्रति व्यक्ति एक किलो के हिसाब से चीनी दी जाएगी। इसे रिवर्स ई-ऑक्शन के मध्यम से खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक(Cabinet meeting) में यह फैसला हुआ। इस योजना में करीब चार लाख टन चीनी खरीदने का अनुमान लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों को चीनी देने का निर्देश राज्यों को दिया है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में ई-टेंडरिंग के मध्यम से चीनी खरीदने का फैसला हुआ था। ई-टेंडरिंग से चीनी लेने में कठिनाई आ रही थी और टेंडर भी कम आ रहे थे। राज्य सरकार ने इसलिए अब रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से चीनी खरीदने का फैसला किया है। रिवर्स ई-ऑक्शन में खुला टेंडर होता है। इसमें डाले गए सबसे कम दर के टेंडर को कोई भी देख कर इससे कम दर पर संशोधित नया टेंडर डाल सकता है।

उन्होंने बताया कि रिवर्स ई-ऑक्शन में अधिक संख्या में चीनी आपूर्तिकर्ता भाग ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धा होने के कारण चीनी की दाम भी कम हो सकते हैं। रिवर्स ई-ऑक्शन के माध्यम से खरीद में समय व लागत ई-टेंडरिंग की अपेक्षा कम आती है। राज्य सरकार ने इस पर विचार-विमर्श के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2018 को संपन्न बैठक में चीनी खरीद रिवर्स ई-ऑक्शन से करने पर सहमति जताई थी। इसके लिए केंद्र सरकार की एमएसटीसी कंपनी काम करेगी। रिवर्स ई-ऑक्शन मंडलवार किया जाएगा। एमएसटीसी कंपनी केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाली मिनी रत्न कंपनी है। कंपनी रिवर्स ई-ऑक्शन के लिए मंडलवार ई-पोर्टल बनाएगी।

अनाथ बच्चों को मिलेगा घर, सरकार लोगों को गोद लेने के लिए करेगी प्रोत्साहित

नई दिल्ली। गोद लेने को इच्छुक दंपत्तियों को केंद्र सरकार बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे अनाथ बच्चों और परित्यक्त बच्चे को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार चाहती है कि इन बच्चों का डेटा केंद्रीय दत्तक रिसोर्स अथारिटी (कारा) के अंतर्गत चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इन्फार्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम से जोड़ा जाए। इससे लोगों को इन बच्चों के बारे में ज्यादा जानकारी होगी और वे इन्हें गोद लेने को प्रोत्साहित हों।

बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभाओं को निखारने और इनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हौसला नाम से संचालित किया जा रहा कार्यक्रम सरकार की इसी मुहिम का हिस्सा है। लेकिन सरकार चाहती है कि अगर इन बच्चों को बेहतर परवरिश का कोई मौका मिल सकता है तो यह कोशिश गंभीरता से की जानी चाहिए।

राज्यों के बाल संरक्षण आयोग को सलाह

सूत्रों के मुताबिक महिला व बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव ने पिछले दिनों राज्य बाल संरक्षण आयोग को इस तरह का परामर्श दिया है कि वे सीसीआई में रहे रहे अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए उचित कदम उठाएं। सचिव ने यह सलाह भी दी है कि इन बच्चों के गैर संस्थागत देखभाल पर भी जोर देना चाहिए। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि बाल देखभाल केंद्रों में बहुत से बच्चे किसी अनहोनी के कारण रहने को मजबूर होते हैं। या तो उनके माता पिता में से कोई नहीं होता या फिर वे छोड़ दिए जाते हैं और उनके मां बाप का पता नहीं होता। यह बच्चे एक अहाते के भीतर ही अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर होते हैं।

85 हजार परित्यक्त बच्चे

देश भर में करीब आठ हजार बाल देखभाल संस्थान-सीसीआई हैं। इनमें से करीब 2200 सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं। यहां रह रहे कुल बच्चों की संख्या करीब 80 से 85 हजार के बीच है। सूत्रों का कहना है कि कानूनी वजहों से इन संस्थानों में रखे गए बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के लिए सरकार बिना किसी कानूनी अड़चन के बेहतरी के कदम उठा रही है।

»» एनपीएस में सरकारी योगदान में चार फीसद की बढ़ोतरी

जाते जाते पेंशनरों को तोहफा दे गया यह साल

नई दिल्ली एजेंसी। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए एनपीएस में अपना योगदान चार फीसद बढ़ा दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन पण्राली (एनपीएस) के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही सेवानिवृति पर एनपीएस से की जाने वाली निकासी को भी पूरी तरह से कर मुक्त बना दिया गया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पिछले सप्ताह हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। फैसले के मुताबिक एनपीएस में केन्द्र सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जायेगा। योजना के तहत कर्मचारी का न्यूनतम योगदान उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत होता है।

जेटली ने यहां संवाददाताओं को बताया, ''कर्मचारियों के व्यापक हित में यह बदलाव किया गया है।

' एनपीएस में सरकार के योगदान में की गई वृद्धि से सरकारी खजाने पर 2019- 20 में 2,840 करोड़ रपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

एनपीएस के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र है।

शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है।

वित्त मंत्री ने कहा कि योजना से बाहर होते समय निकाली जाने वाली 60 प्रतिशत राशि को कर मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही एक तरह से पूरी राशि की निकासी कर मुक्त हो गई है। एनपीएस के अंशधारक को योजना में जमा राशि में से सेवानिवृति के समय 60 प्रतिशत राशि की निकासी में से 40 प्रतिशत कर मुक्त थी जबकि शेष 20 प्रतिशत पर कर लिया जाता है। बहरहाल, अब पूरी 60 प्रतिशत निकासी को कर मुक्त कर दिया गया है।

यह व्यवसथा सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए की गई है।

लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि एनपीएस को भी ई-ई-ई यानी अंशदान पर-निवेश-प्रतिफ ल और निकासी तीनों स्तर पर कर में छूट हो जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजनाओं के मामले में है।

संपादकीय

सीटों का बंटवारा

केंद्रीय मंत्रिमंडल से उपेन्द्र कुशवाहा का इस्तीफा तथा रालोसपा का राजग से अलग होने पर अचरज का कोई कारण नहीं है। कुछ समय से इसके संकेत मिल रहे थे कि भाजपा बिहार में रालोसपा को पिछली बार की तरह लोक सभा चुनाव में तीन सीटें देने को तैयार नहीं थी। जद यू और भाजपा के बीच 17-17 सीटों पर समझौता हो जाने के बाद छह सीटें बच रही हैं, जिनमें रामविलास पासवान की लोजपा तथा रालोसपा, दोनों को समन्वित करना था। इसमें पिछली बार की तरह दोनों को सीटें दिया जाना संभव न था। हालांकि कुशवाहा एवं नीतीश कुमार के लिए अभी तक बिहार की राजनीति में एक साथ रहने का सहज वातावरण नहीं बना है। नीतीश के खिलाफ विद्रोह करके ही कुशवाहा जद यू से अलग हुए तथा राज्य सभा की सदस्यता छोड़ी थी। चूंकि नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ दिया था, इसलिए इन सबका साथ आना संभव हो सका। अब जब नीतीश भाजपा के साथ आ गए हैं, तो कुशवाहा के लिए वैसे भी राजग में असहज स्थिति पैदा हो गई थी। दोनों के बीच कुछ बयानवाजी भी हुई। भाजपा ने भी कुशवाहा को ज्यादा महत्त्व नहीं दिया। जब जद यू और भाजपा ने आपस में सीटों का बंटवारा किया उस समय उनको अहसास था कि शेष दोनों घटकों के अंदर असंतोष पैदा होगा। तो इस स्थिति के लिए दोनों मानसिक रूप से तैयार होंगे। हालांकि उन्होंने उस दिन राजग का दामन छोड़ा है, जिस दिन भाजपा विरोधी दलों की बैठक हो रही है तथा एक दिन बाद संसद का अधिवेशन होने वाला है। जाहिर है, दिन का चयन उन्होंने सोच-समझकर किया और सारे विकल्प खुले रखने का ऐलान भी कर दिया। जो स्थिति है उसमें उनके राजग विरोधी गठबंधन में जाने की पूरी संभावना है। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। इसका असर बिहार की राजनीति पर होगा। कुशवाहा ऐसी जाति का प्रतिनिधत्व करते हैं, जिसका बिहार की राजनीति में असर है। सामाजिक समीकरणों में राजग से उस जाति का वोट अलग होने की भरपाई कैसे होगी? जिस गठबंधन के साथ जुड़ेंगे उसमें वह वोट जोड़ सकते हैं। इस तरह बिहार में राजद, कांग्रेस और रालोसपा का एक मजबूत गठबंधन राजग के खिलाफ होगा। इसका राष्ट्रीय महत्त्व केवल इतना है कि विपक्ष इसे राजग में व्याप्त असंतोष के रूप में प्रचारित करेगा जिसका सहमतिकारक जवाब भाजपा नहीं दे पाएगी।

हमारा अधिकार है

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित धर्मसभा से निकला संदेश वही है जो अयोध्या और नागपुर की प्रमुख धर्मसभाओं से बाहर आ चुका था। विहिप और संतों ने देश में करीब 200 सभाएं करने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए दिल्ली का दरवाजा फिर खटखटाया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी की इस बात की अनदेखी मोदी सरकार के लिए कठिन है कि ''हम राम मंदिर की भीख नहीं मांग रहे, यह हमारा अधिकार है।' जोशी से पहले नागपुर की धर्मसभा और उससे पहले विजयादशमी के वार्षिक संबोधन में सरसंघचालक मोहन भागवत भी सरकार से मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि कई साधु-संतों की तरह जोशी ने सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना नहीं की, बल्कि कहा कि न्याय व्यवस्था व न्यायालय की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। न्याय व्यवस्था व राजसत्ता, दोनों को अपने पूरे सामर्य का प्रयोग करते हुए जनभावना की उपेक्षा के स्थान पर उसका सम्मान करना चाहिए। इसका अर्थ भी यही था कि जितनी जल्दी हो अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की अनुमति मिले। करीब दो दशक बाद दिल्ली में राममंदिर निर्माण को लेकर साधु-संतों तथा रामभक्तों की इतनी विशाल सभा हुई है। भारी संख्या में दिल्ली आने का उद्देश्य सत्ता पर दबाव बनाना ही हो सकता है। न्यायालय तो दबाव में काम कर नहीं सकता, लेकिन जो शासन में हैं, उन्हें वोट चाहिए। इस संदर्भ में संतों की चेतावनी साफ थी, या तो मंदिर बनाने में मदद यानी कानून बनाकर मंदिर की अनुमति दीजिए या हमारे विरोध का सामना करने को तैयार रहिए। जोशी ने कहा भी कि जो आज सत्ता में हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाने का वादा किया था। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनके सहयोगियों को धर्मसभा से निकलने वाले स्वरों का आभास नहीं था। किंतु सरकार में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के बीच कानून बनाने के लिए विधेयक लाने में उन्हें हिचक होगी। राजग में जद यू जैसे दल हैं, जिनके लिए भाजपा के इस कदम का समर्थन करना कठिन होगा। बावजूद इसके भाजपा के लिए भारत भर से उठती आवाज और दिल्ली तक पहुंची सामूहिक प्रतिध्वनि को नजरअंदाज करना साख को खत्म करने जैसा होगा।

न्यायाधीशों प्रत्यर्पण का आदेश

रक्षा सौदा दलाली के आरोप में आजादी के बाद के जीप खरीद घोटाला से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर कांड तक पहली बार भारत को किसी आरोपित को पकड़ लाने में सफलता मिली है। बोफोर्स कांड में ओट्टाविया क्वात्रोच्चि को न ला पाने की छटपटाहट भारत के उन लोगों में आज भी है, जिन्होंने उस पर काम किया था। उन्हें पता है कि उस सौदे में दलाली ली गई थी। बहरहाल, अब चूंकि ऐसा व्यक्ति हमारे हाथों है, जिस पर आरोप है कि उसने सौदा पक्का कराने के लिए सैन्य अधिकारियों, नौकरशाहों तथा नेताओं को घूस दी थी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि सच सामने आएगा। हालांकि देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। लेकिन न भूलें कि सब कुछ न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ है। दिल्ली मिशेल का केंद्र रहा है। 2012 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर में घूस का आरोप सामने आने के बाद वह निकल भागा था।

सतीश पेडणोकर

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स का प्रत्यर्पण कुछ दिनों पूर्व हुआ होता तो निश्चय ही काफी समय तक मीडिया में चर्चा का विषय रहता। किंतु उसका लाया जाना विधानसभा चुनावों के समय हुआ इसलिए सुर्खियों से गायब हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि उसका प्रत्यर्पण महत्त्वपूर्ण नहीं है। रक्षा सौदा दलाली के आरोप में आजादी के बाद के जीप खरीद घोटाला से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर कांड तक पहली बार भारत को किसी आरोपित को पकड़ लाने में सफलता मिली है। बोफोर्स कांड में ओट्टाविया क्वात्रोच्चि को न ला पाने की छटपटाहट भारत के उन लोगों में आज भी है, जिन्होंने उस पर काम किया था। उन्हें पता है कि उस सौदे में दलाली ली गई थी। बहरहाल, अब चूंकि ऐसा व्यक्ति हमारे हाथों है, जिस पर आरोप है कि उसने सौदा पक्का कराने के लिए सैन्य अधिकारियों, नौकरशाहों तथा नेताओं को घूस दी थी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि सच सामने आएगा।

देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। लेकिन न भूलें कि सब कुछ न्यायालय के आदेश के अनुसार हुआ है। दिल्ली मिशेल का केंद्र रहा है। 2012 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर में घूस का आरोप सामने आने के बाद वह निकल भागा था। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय ने 24 सितम्बर, 2015 को उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उसे फरवरी, 2017 में दुबई में गिरफ्तार किया गया। जब भारत पहुंचते ही उसके लिए वकील खड़े हो गए तो संयुक्त अरब अमीरात में उसके पास कानूनी लड़ाई की पूरी ताकत थी। बावजूद वह कानूनी लड़ाई में पराजित किया जा सका तो इसीलिए कि भारत ने पूरी ताकत लगाई तथा नीचे से शीर्ष न्यायालय में जो आरोप पत्र, गवाहों के बयान, अन्य साक्ष्य एवं दस्तावेज दिए गए वे इतने सशक्त थे कि न्यायाधीशों प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया।

राजनयिक कोशिशें पहले से चल रही थीं अन्यथा हम आसानी से वहां कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ पाते। मामला जीतने के बावजूद उसका प्रत्यर्पण संभव नहीं होता। यह विवरण इसलिए आवश्यक है ताकि साफ हो जाए कि जैसा वातावरण बना दिया गया है कि उसे तो बस पकड़ लाना था, अब राजनीतिक लाभ पाने का समय है, तो ला दिया गया वह सच नहीं है। उसे लाना इतना बहुत कठिन था।

नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद इसकी जांच तेज हुई और तब से एजेंसियां पीछे थीं। 8 फरवरी, 2010 को रक्षा मंत्रालय ने ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ वायुसेना के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का समझौता किया था। इटली की फिनमैकेनिका कंपनी उसके लिए हेलिकॉप्टर बनाती है। इनमें से 8 का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की उड़ान के लिए किया जाना था। कुल सौदा 55.62 करोड़ यानी करीब 3726 करोड़ का था। भारत में तीन हेलिकॉप्टर आ भी गए। किंतु इटली से यह खबर आई कि भारतीय अधिकारियों एवं नेताओं को सौदे की करीब 10 प्रतिशत घूस दी गई है। फिनमेकैनिका के पूर्व उपाध्यक्ष जुगेपी ओरसी और अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रूनो स्पाग्नोलिनी के खिलाफ वहां की जांच एजेंसियों ने 2012 में मामला दर्ज किया। 2016 में निचले न्यायालय ने ब्रूनो को चार और ओरसी को साढ़े चार साल की सजा सुनाई। इटली में जांच शुरू हो गई तो आनन-फानन में सौदा रद्द हुआ तथा जांच का आदेश दिया गया। यूपीए सरकार इतनी घबरा गई कि कंपनी को काली सूची में डाल दिया जबकि आजादी के बाद से ही उससे हेलिकॉप्टर लिए जा रहे हैं। भारत में 50 प्रतिशत से ज्यादा हेलिकॉप्टर उसी कंपनी के हैं। काली सूची में डालने के बाद कल-पुजरे तक का संकट पैदा हो रहा था। टाटा उसके साथ संयुक्त उद्यम लगा रहा था, वह भी रुक गया। मोदी सरकार ने जांच जारी रखी, लेकिन कंपनी को काली सूची से हटा दिया। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी तक को गिरफ्तार किया। भारत में पहली बार हुआ जब सेना के सर्वोच्च अधिकारी रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। 18 लोगों को आरोपित बनाया गया। तेरह के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। आरोप पत्र पढ़ें तो साफ हो जाएगा कि मिशेल ने घूस की रकम ट्रांसफर करने के लिए दो कंपनियों ग्लोबल सर्विसेज एफजेडई, दुबई और ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स सर्विसेज, लंदन का इस्तेमाल किया।

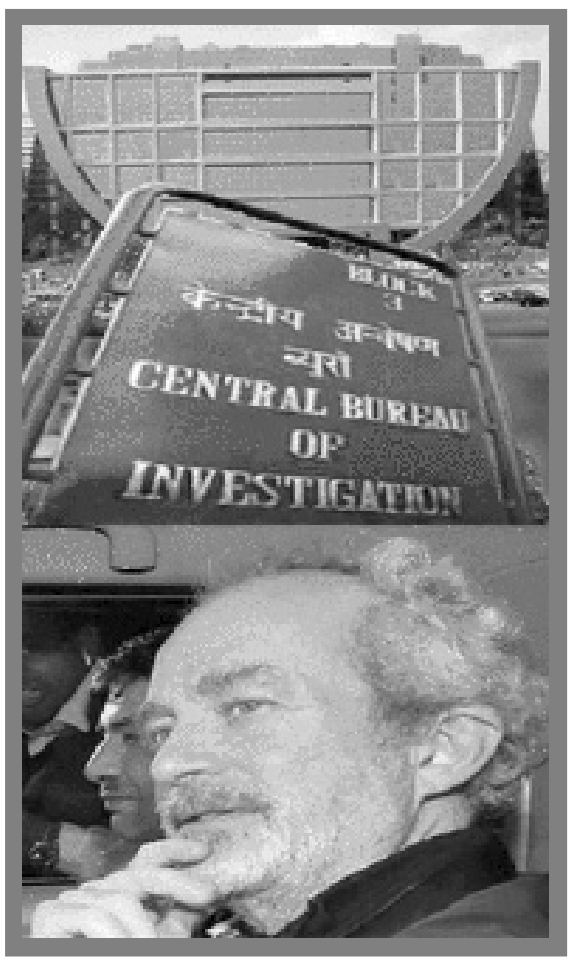

मिशेल का कहना है कि वह रक्षा सामग्री के विशेषज्ञ के तौर पर परामर्श देता है। बिचौलिए रक्षा सामग्री के जानकार और निर्माता कंपनियों के परामर्शदाता होते हैं। जिन देशों में काम करते हैं, वहां उत्पादन बिकवाने में सहयोग करते हैं। जहां आसानी से सौदा नहीं हुआ तो पटाने के लिए सब कुछ होता है। त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने घूस लेकर हेलिकॉप्टरों की ऑपरेशनल क्षमता की ऊंचाई 6 हजार मीटर रखने के मानक को घटाकर 4500 मीटर तथा केबिन की ऊंचाई 1.8 मीटर कर दी थी। इससे अगस्ता वेस्टलैंड को सौदा मिल सका। त्यागी का कहना है कि यह फैसला वायुसेना, एसपीजी सहित दूसरे विभागों ने संयुक्त रूप से लिया तथा उनके काल में सौदा हुआ भी नहीं। यह संभव नहीं है कि केवल अधिकारियों के स्तर पर फैसला हो गया हो इटली के निचले न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें 15 पृष्ठ भारत सरकार, कांग्रेस के नेताओं और रक्षा मंत्रालय पर केंद्रित हैं, जिनमें तीखी टिप्पणियां हैं। सिग्नोरा गांधी का नाम दो बार आया है, जिनके बारे में कहा है कि सौदे में उनकी बड़ी भूमिका थी। सीबीआई को हाथ से लिखा दस्तावेज मिला जिसमें संकेत नाम हैं। मसलन, पीओल जिसे हम पोलिटिशयन और बीयूआर जिसे ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। एपी, ओएफ.जैसे नाम हैं। इटली के निचले न्यायालय ने अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस, सोनिया गांधी सबका नाम लिखा है। मिशेल से सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय नेताओं के नाम कहलवाने में सफलता पा लें तो राजनीतिक विस्फोट की स्थिति पैदा होगी। तर्क दिया जा रहा है कि 8 जनवरी, 2018 को इटली की अपील्स कोर्ट ने जुगेपी ओरसी और ब्रुनो स्पाग्नोलिनी को जब बरी कर दिया तो मामले में कुछ है ही नहीं। वहां के न्यायालय ने सिर्फ इतना कहा है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए। उसके आधार पर मामला बंद करने का कोई कारण नहीं है। कई कारणों से वहां ऐसा हुआ होगा।

चलते चलते

कारोबारी समूह

चीन में लगता है कि कम्युनिज्म की नई रणनीति है कि चुनिंदा कारोबारियों के पास दुनिया-जहान की पूंजी जमा हो जाए। कुछेक चीन के आधिकारिक कम्युनिस्टों पर आ जाएगी और इस तरह से पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ ने कभी कहा था-हजारों फूलों को खिलने दो।

''पीपुल्स डेली' ने बताया कि भारतीय कंपनी पेटीएम से जुड़े और ग्लोबल कारोबारी जैक मा कम्युनिस्ट हैं। जैक मा की निजी हैसियत दो लाख करोड़ रु पये से ज्यादा की है। यानी जैक मा ने बहुत पूंजी इकट्ठी कर मारी है। पर कम्युनिज्म तो निजी पूंजी का विरोधी है। चीन में लगता है कि कम्युनिज्म की नई रणनीति है कि चुनिंदा कारोबारियों के पास दुनिया-जहान की पूंजी जमा हो जाए। कुछेक चीन के आधिकारिक कम्युनिस्टों पर आ जाएगी और इस तरह से पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ ने कभी कहा था-हजारों फूलों को खिलने दो। जैक मा नई चाल के कम्युनिस्ट हैं। कहते हैं-हजारों नहीं, अरबों-खरबों की रकम को बनने दो। रकम बन रही है सब तरफ। कम्युनिस्टों में भी, कम्युनिस्ट विरोधी राजनीति में। आम आदमी सिर्फ बनाया जा रहा है। खबरें हैं कि चीन में जैक मा की तरह के कई अरबपति कम्युनिस्ट हैं। अरबों के प्रापर्टी कारोबारी जू जियान हैं, वांडा कारोबारी समूह के वांग जियालिन हैं, सब कम्युनिस्ट हैं, सब पूंजीपति हैं। कार्ल माक्स ने कहा था कि पूंजीपति मजदूरों का हक मारकर पूंजी मुनाफों को बड़ा कर सकते हैं। चीन में पूंजीपतियों को मजदूरों का हक मारने की जरूरत आम तौर पर नहीं पड़ती क्योंकि चीन में मजदूरों के हक जैसी कोई चीज न होती। मजदूरों को हड़ताल का हक नहीं है। जैक मा जैसे सुपर कम्युनिस्ट चीन में ही हो सकते हैं। फिर जैक मा से जुड़े भारतीय कारोबारों को फिर क्या माना जाए-जी उन्हें भी आधिकारिक कम्युनिस्ट संस्थान माना जाए। जी उन संस्थानों के कर्मचारी जैक मा की पूंजी से अपने हिस्से की मांग करें तो क्या माना जाए। इस मांग को भी कम्युनिस्ट मांग माना जाए। हिस्सा मांगने वाले भी कम्युनिस्ट और हिस्सा दबाने वाले भी कम्युनिस्ट। कार्ल माक्स कह गए थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। दुनिया के मजदूर मिल कर इतना न जमा कर पाए जितना जैक अकेले जमा कर गए हैं। तो सबसे कामयाब कम्युनिस्ट किसे माना जाए-जैक मा को। सबसे कामयाब कम्युनिस्ट अगर जैक मा हैं, तो माओ क्या हैं। माओ की आत्मा ने अपने नारे को बदल दिया है-अरबों-खरबों कुछेक के हाथों में बनने दो, जैक मा की कसम।

फोटोग्राफी...

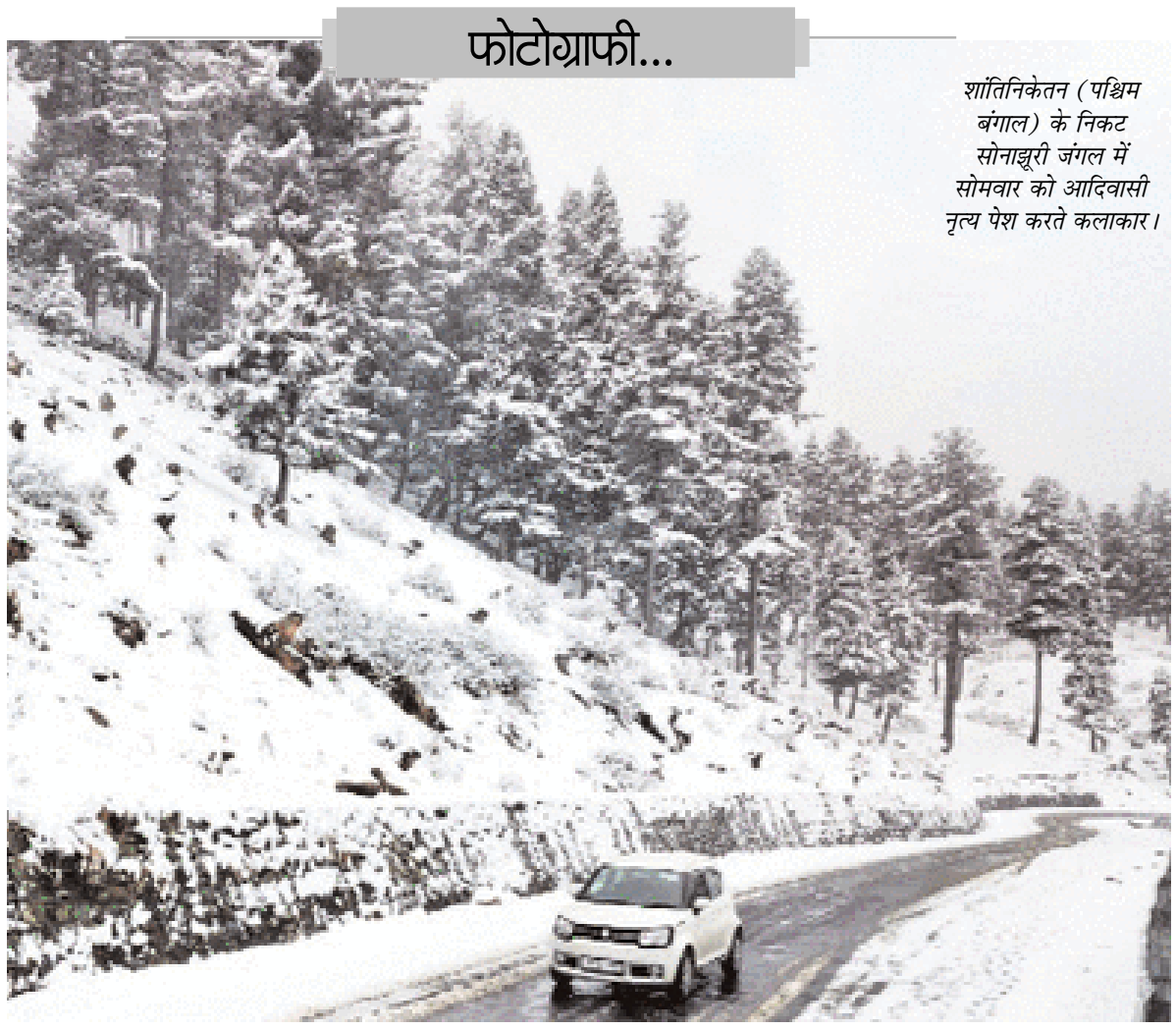

शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) के निकट सोनाझूरी जंगल में सोमवार को आदिवासी नृत्य पेश करते कलाकार।

विरोधी केंद्रों में सामूहिक बंदी

युक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन के जिनझियांग प्रांत में 10 लाख उइगर अल्पसंख्यक मुसलमानों को चरमपंथी-विरोधी केंद्रों में सामूहिक बंदी बनाकर रखा गया है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी पुष्टि एक सेटेलाइट विश्लेषण से भी हुई है। चीन का आरोप है कि ये लोग आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अब उइगर मुसलमानों की जान बचाने के लिए 15 पश्चिमी देशों ने चीन को मानवाधिकार हनन के मामले पर घेरने की तैयारी कर ली है। इन देशों के राजदूतों ने जिनझियांग की कांग्रेस पार्टी के प्रमुख को आग्रह पत्र भेजा है। अमेरिका ने कहा है कि दस लाख उइगर मुस्लिमों को पुनर्शिक्षा शिविरों में रखा जाना भयावह है। उन्हें रिहा करना चाहिए जबकि चीन कह रहा है कि ये शिविर व्यावसायिक शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र हैं। लगता है कि चीन किसी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसने हाल ही में कट्टरवाद से प्रभावित इन मुसलमानों को 30 दिन के अंदर आत्मसमर्पण कर अपना अपराध स्वीकार करने का आदेश दिया है। कहा है कि जो लोग इस अवधि में न्यायिक अंग के समक्ष अपने जुर्म को कबूल करेंगे तो उनके साथ नरमी से निपटा जाएगा। सजा भी टाली जा सकती है। चीन का कहना है कि हम अल्पसंख्यकों के धर्म-संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं जबकि विश्व मानव संगठन यह तर्क मानने को तैयार नहीं हैं। इनका मानना है कि शिविरों में रखे गए उइगर मुसलमानों को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वफादारी की शपथ उठवाई जाती है। चीन सरकार का कहना है कि उसे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कई उइगर मुसलमान सीरिया जाकर उग्रवादी समूहों में शामिल हो गए हैं। काबिलेगौर है कि पिछले चार सालों में चीन ने उइगर मुसलमानों पर ज्यादा सख्ती शुरू की है। इन कैंपों में निगरानी के लिए टॉवर व गार्ड रूम और सर्विलांस सिस्टम मौजूद हैं। चेहरा पहचानने वाले, मोबाइल फोन का कंटेंट पढ़ने वाले उपकरण और बायोमैट्रिक डाटा जुटाकर उनकी निगरानी की जा रही है। चीन के केंद्रीय व क्षेत्रीय शासकों ने कई ऐसे कानून भी बनाए हैं जिनके तहत उइगर मुसलमानों की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां अपराध के दायरे में आ गई हैं। चीन का ''आतंकवाद विरोधी कानून (2015)', जिनझियांग प्रांत उइगर स्वायत्त क्षेत्र का आतंकवाद विरोधी कानून (2016) और एक्सयूएआर रेग्युलेशन (2017) उल्लेखनीय हैं। ये कानून स्थानीय प्रशासन को निगरानी और सेंसरशिप के असीमित अधिकार देते हैं। इन कानूनों के तहत उइगर विचारों और उनके कार्यक्रमों पर नजर तो रखी ही जाने लगी है, नकाब व बुर्का पहनने, दाढ़ी बढ़ाने, बच्चों के धर्म से जुड़े नाम रखने, सरकारी टीवी देखने और बच्चों को सरकारी शिक्षा दिलवाने से रोकना भी अपराध समझा जाता है।''डबललिंक्ड हाऊसहोल्ड सिस्टम' भी शुरू किया गया है, जो घरों में तांक-झांक की अनुमति देता है। उइगर मुसलमानों के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। विदेश में पढ़ रहे अधिकांश उइगर युवकों को वापिस बुलवाकर हिरासत में रखने के बाद गायब कर दिया गया है। उनका कुछ पता नहीं है कि वे जिंदा हैं, या मर गए। चीन की सरकार को इस पश्चिमी प्रांत जिनझियांग में दस लाख उइगर मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर की जा रही दमन कार्रवाई के लिए अल्पसंख्यकों के भविष्य पर अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए वरना उसकी दमनकारी नीति को लेकर असंतोष और बढ़ेगा।

सत्संग

अंहकार

असंभव है। अहंकार का त्याग नहीं किया जा सकता क्योंकि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार केवल एक विचार है: उसमें कोई सार नहीं है। तुम इस पर भरोसा करके इसे वास्तविकता दे देते हो। तुम भरोसा छोड़ सकते हो और वास्तविकता गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अहंकार एक तरह का अभाव है। अहंकार अंधकार के समान है; अंधकार का अपना कोई सकारात्मक अस्तित्व नहीं होता; यह बस प्रकाश का अभाव है। तुम अंधकार को कमरे के बाहर नहीं फेंक सकते; बाहर नहीं निकाल सकते, उसे भीतर नहीं ला सकते। तुम अंधकार के साथ सीधे-सीधे कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें प्रकाश के साथ कुछ करना होगा। यदि तुम प्रकाश करो तब अंधेरा नहीं रह जाएगा; यदि तुम प्रकाश बुझा दो, वहां अंधेरा है। अंधकार प्रकाश का अभाव है, अहंकार भी ऐसा ही है: आत्मज्ञान का अभाव। तुम्हें बार-बार कहा गया है: ''अपने अहंकार को मारो'-और यह वाक्य साफ तौर पर बेतुका है, क्योंकि जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसका त्याग भी नहीं किया जा सकता। यदि उसका त्याग करने की कोशिश भी करोगे, जो उपस्थित ही नहीं है, तो तुम एक नया अहंकार पैदा कर लोगे-विनम्र होने का अहंकार, निरहंकार होने का अहंकार, उस व्यक्ति का अहंकार जो सोचता है कि उसने अपने अहंकार का त्याग दे दिया। यह फिर से एक नये प्रकार का अंधकार होगा। नहीं, मैं तुमसे अहंकार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। इसके विपरीत, कहूंगा कि देखने की कोशिश करो की अहंकार है कहां? इसकी गहराई में देखो; इसे पकड़ने की कोशिश करो कि आखिर, यह है कहां? वास्तविकता में है भी या नहीं। किसी भी बात के विरोध में जाने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार तुम्हारा अनुभव है-स्पष्ट दिख सकता है। तुम्हारा पूरा जीवन अहंकार की घटनाओं के आसपास घूमता है। इसका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं। इसमें गहरी डुबकी लगाओ, भीतर प्रवेश करो। इसमें प्रवेश करने का अर्थ है अपने घर में जागरूकता ले आना, अंधकार में प्रकाश ले आना। आखिर, कैसे यह संचालित करता है। जब तुम अपने भीतरतम के केंद्र में प्रवेश कर जाते हो, तुम कुछ बिल्कुल ही अलग बात पाओगे जो कि अहंकार नहीं है। यह स्वयं का भाव है, स्वयं की पराकाष्ठा है-यह भगवत्ता है। तुम अब एक अलग सत्ता के रूप में मिट गए; अब तुम कोई निर्जन द्वीप नहीं हो, तुम पूर्ण का हिस्सा हो।

सार समाचार

थाईलैंड की सरकार ने चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक प्रचार पर लगी रोक हटाई

थ्रबैंकॉक। थाइलैंड की सैन्य सरकार ने 2019 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक प्रचार पर से प्रतिबंध हटा दिया है। रॉयल गजट की ओर से मंगलवार को प्रकाशित एक आदेश में यह बात कही गई है। आदेश में कहा गया, ''राजनीतिक दल अपनी योजनाओं को पेश करने के लिए अब प्रचार कर पाएंगे।'' यह आदेश तत्काल लागू होगा। देश में अगले साल 24 फरवरी को चुनाव होने हैं।ईलैंड की सरकार ने चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक प्रचार पर लगी रोक हटाई

यमन में दो करोड़ लोग भूखे हैं, ढ़ाई लाख लोग कर रहे हैं तबाही का सामना

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि युद्ध प्रभावित यमन में दो करोड़ लोग भूख का और कम से कम ढ़ाई लाख लोग तबाही का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता के प्रमुख मार्क लोकॉक ने संवाददाताओं को बताया कि देश में तेजी से हालात खराब हो रहे हैं और यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पहली बार यमन के ढ़ाई लाख लोगों को वैश्विक स्केल पर फेज -5 में रखा गया है। यह स्केल खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण की भयावहता को दर्शाता है। इस स्केल में फेज -5 भुखमरी, मौत और गरीबी को दर्शाता है। लोकॉक और संयुक्त राष्ट्र में मानवीय मामलों के अवर महासचिव ने कहा है कि ये लोग चार प्रांतो ताएज , सादा , हज्जा और हेदोदिया में रह रहे हैं जहां संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है।

ताइवान में हुवावेई नेटवर्क के उपकरणों पर प्रतिबंध

ताइपे। ताइवान ने सुरक्षा चिंताओं के बीच चीनी कंपनी हुवावेई और जेडटीई के नेटवर्क उपकरणों पर अपना पांच वर्ष पुराना प्रतिबंध और मजबूती के साथ लगाया है। सप्ताहांत में अधिकारियों ने सांसदों और जनता को फिर आश्वस्त किया कि इस तरह के उपाय प्रभावी रहे हैं और संचार क्षेत्र को खतरा न्यूनतम हुआ है। जहां कई अन्य देशों में भी हुवावेई पर इस तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं वहीं ताइवान में यह संकट अधिक गहरा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता रहा है और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए सैन्य कार्रवाई की भी धमकी भी देता रहा है। गौरतलब है कि हुवावेई की मुख्य वित्तीय अधिकारी मेंग वानझोऊ पर ईरान के साथ कारोबार पर अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्हें वैंकूवर में एक दिसंबर को हिरासत में लिया गया था। सोमवार को सांसदों ने हुवावेई पर प्रतिबंध का विस्तार करने की मांग की।

विदेशियों को गैरकानूनी तरीके से अमेरिका लाने के मामले में भारतीय गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमेरिका में 38 वर्षीय भारतीय नागरिक को धन ऐंठने की मंशा से विदेशी लोगों को अवैध तरीके से यहां पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यू जर्सी अमेरिकी अटॉर्नी क्रेग कार्पेनिटो ने सोमवार को बताया कि भाविन पटेल पर व्यवसायिक विमानों से विदेशी नागरिकों की तस्करी कर उन्हें अमेरिका लाने के छह आरोप हैं और उन्हें शरण देने का एक आरोप है। उसे अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जॉन माइकल वैजकूज के समक्ष 18 दिसम्बर 2018 को पेश किया जाएगा। अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) और गृह सुरक्षा जांच (एचएसआई) के विशेष एजेंटों ने उन्हें सात दिसम्बर को नेवार्क लिबर्टी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया था। दोषी पाए जाने पर पटेल को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

जानें, ट्रंप के किस सपने का वैज्ञानिक भी कर रहे हैं विरोध- सियासी 'दीवार' पर महासंग्राम

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका में मेक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण को लेकर एक सियासी महासंग्राम चल रहा है। अमेरिका के राष्?ट्रपति डोनाल्?ड ट्रंप ने इस मुद्दे को अपनी नाक का विषय बना रखा है। हालांकि, राष्?ट्रपति चुनाव में प्रचार के दौरान उन्?होंने अमेरिकी जनता से इस दीवार को बनाने का वादा किया था। आइए जानते हैं कि आखिर दीवार के पीछे का सच क?या है। अमेरिका में इसे लेकर क?यों हंगामा मचा है। इसके अलावा इसके भौगोलिक, सामाजिक संदर्भों के साथ वैज्ञानिकों के विरोध का कारण भी जानेंगे।

अवैध प्रवासी अमेरिका के लिए खतरा

हर साल करीब साढ़े तीन लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में दाखिल होते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या मेक्सिको से आने वालों की है। सीमा पार से लगातार अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, खतरनाक गिरोहों एवं अंतरराष्ट्रीय अपराधिक संगठनों की गतिविधियां और अवैध इमीग्रेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह केवल अमेरिकी समुदाय और बच्चों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। अमेरिकी कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्श (सीबीपी) के डाटा के अनुसार सीमा गश्ती दल ने मार्च में दक्षिण पश्चिम सीमा पर रिकॉर्ड 37,393 लोगों को गिरफ्तार किया था।

अमेरिका-मेक्सिको की संवेदनशील सीमा 3,200 किमी लंबी

दरअसल, अमेरिका और मेक्सिको की संवेदनशील सीमा करीब 3,200 किलोमीटर लंबी है। इसमें से लगभग 1,100 किलोमीटर पर अब तक बाड़ लगाने का काम हो चुका है। ये सीमा चार अमेरिकी राज्यों और छह मेक्सिकन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें रेगिस्तानी इलाकों से लेकर बड़े शहर तक आते हैं। न्यू मेक्सिको में एक छोटी दूरी को घेरना ही मुश्किल है। वहीं कुछ दूसरी जगहों पर सीमा सुरक्षा बल के लोग निगरानी रखते हैं।

ट्रंप ने कहा था- मैं एक शानदार दीवार बनाउंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के समय ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर मैं एक शानदार दीवार बनाउंगा। मुझसे अच्छी दीवार तो कोई बना नहीं सकता। मैं मेक्सिको से इसका खर्च वसूलूंगा। चुनावी रैली के दौरान ट्रंप ने मेक्सिको से आने वालों में ज्यादातर के ड्रग्स और अपराध साथ लाने का आरोप लगाया था। ट्रंप मेक्सिको के साथ लगी अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया की सबसे बड़ी निर्माण योजना होगी। हालांकि, कई सालों से बॉर्डर पर स्टील के कांटेदार तारों को लगाने का प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हुआ है।

मेक्सिकोवासियों का अमेरिका जाने का सपना टूटा

अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले ऐसे मेक्सिकन लोगों का परिवार पीछे रह जाता है। वे न तो अपने परिवार को अमेरिका ला सकते हैं और न ही अपना जीवन बेहतर करने के लिए कोई अच्छी नौकरी कर पाते हैं। दो देशों के बीच बनी बाड़ से अलग हुए परिवार कभी एक दूसरे को गले नहीं लगा पाते। कई बार ऐसे खास आयोजन किए जाते हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की अंगुलियां छू पाते हैं। रेगिस्तानी रास्ते पार करते हुए सीमा पर पहुंचे कई मेक्सिकोवासियों का अमेरिका जाने का सपना करीब जाकर टूटता है और वे जेल जा पहुंचते हैं। कई लोग मानव तस्करों को सीमा पार करवाने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। कई बार इन्हें सीमा पार करते हुए गोली मार दी जाती है।

सीमा दीवार के खिलाफ खड़े हुए वैज्ञानिक

अमेरिका-मेक्सिको की लंबी सीमा पर दीवार को लेकर राजनीतिक और सामाजिक पहलू चाहे जो हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस दीवार का खुलकर विरोध किया है। आखिर इस विरोध की वजह क्या है। वैज्ञानिकों का मत है कि इस दीवार से इंसानों के साथ-साथ यहां के जीव-जंतुओं पर भी विपरीत असर पड़ेगा। इनका मानना है कि इससे कई दुर्लभ प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। इसका प्रभाव दोनों देशों की जैव विविधता पर पड़ेगा। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने अब इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है।

मेक्सिको सीमा पर जैव विविधता का संकट

उनका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों की करीब एक हजार प्रजातियां सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। बड़े सींगों वाली भेड़, ग्रे रंग वाला भेड़िया और सोनोरन हिरण जैसी दुर्लभ प्रजातियों की संख्या में कमी आएगी। हो सकता है कि अमेरिका में जगुआर और तेंदुए पूरी तरह विलुप्त हो जाएं। बायोसाइंस जर्नल में छपे लेख के मुताबिक, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दीवार और कंटीली तारों की वजह से जानवरों को पीने के पानी, खाने और साथी के साथ रहने में मुश्किलें आएंगी।

विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश कोर्ट के फैसले का मुंबई के लोगों ने किया स्वागत

मुंबई (एजेंसी)।

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश आने के कुछ ही घंटों बाद मुंबई के प्रतिष्ठित लोगों ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया और कहा कि यह आर्थिक अपराधियों को एक कड़ा संदेश देगा. माल्या करीब 9,000 करोड़ रूपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है. सोमवार शाम वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की न्यायाधीश एम्मा आर्बुथनोट ने माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश किया.

नौकरशाह से नेता बनी आभा सिंह ने कहा कि माल्या का प्रत्यर्पण भारतीय कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करेगा और आर्थिक अपराधियों को यह संदेश भी देगा कि वे अपने देश के लोगों को धोखा देकर भाग नहीं सकते. उन्होंने कहा कि इस अदालती आदेश ने देश को और अधिक मजबूत बना दिया है और हीरा कारोबारी नीरव मोदी तथा

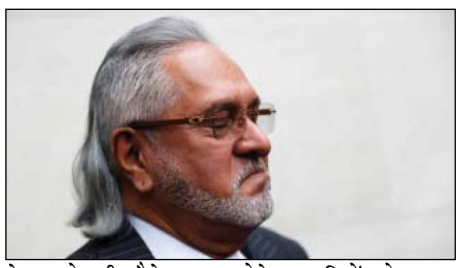

मेहुल चोकसी जैसे अन्य भगोड़े अपराधियों को वापस स्वदेश लाने में इससे मदद मिलेगी. नीरव और चोकसी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब 13,000 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी हैं.

मुंबई उत्तर-पूर्व से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लोकसभा सदस्य किरिट सोमैया ने कहा, ''मोदी सरकार ने विजय माल्या को हासिल कर लिया है. यह कार्रवाई की शुरूआत है. दिवालिया संहिता ने नतीजे दिखाना शुरू कर दिया है. एस्सार स्टील और भूषण स्टील के मुद्दे हल हो गए हैं और अब घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है.''

मुंबई कांग्रेस प्रमुख संजय निरूपम ने माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश अदालत का आभार जताते हुए कहा कि इस कारोबारी के देश छोड़ कर भागने पर अपने पहले के आरोपों पर वह अडिग हैं.

उन्होंने कहा, ''मुझे आशा है कि माल्या से पूरा पैसा बरामद कर लिया जाएगा और बैंकों को अपना बकाया मिल जाएगा. लेकिन मैं अब भी अपने आरोपों पर अडिग हूं कि 'लुक आउट नोटिस' क्यों हटाया गया और उसे (माल्या को) क्यों भाग जाने दिया गया? '' सामाजिक कार्यकर्ता मयंक गांधी ने माल्या को प्रत्यर्पित कराने के लिए सरकारी एजेंसियों के एक मजबूत मामला बनाने की कोशिशों की सराहना की. मयंक ने कहा, ''एजेंसियों (सीबीआई सहित) ने अदालत में इस मामले को मजबूती से पेश करने के लिए काफी मेहनत की. कहीं ना कहीं, सरकार ने भी दबाव बनाया.''

रियल एस्टेट कंपनी के मालिक बने चीन के सबसे अमीर शख्स, जैक मा को पीछे छोड़ा

बीजिंग (एजेंसी)।

एक रियल एस्सेट कंपनी के मालिक 36.7 अरब डॉलर की नेट बर्थ के साथ चीन में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने अलीबाबा के को-फाउंडर जैक मा को पीछे छोड़ दिया है. सोमवार को यह जानकारी दी गई.

समाचार एजेंसी एफे न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि एवरग्रैड ग्रुप के मालिक शू जियायिन करीब 42.5 अरब डॉलर के मालिक हैं, जबकि जैक मा की संपत्ति 35.4 अरब डॉलर और टेनसेंट के संस्थापक पोनी मा हुआटेंग की संपत्ति 35.3 अरब डॉलर है.

फोर्ब्स की रियल-टाइम रैंकिंग में दुनिया के अरबपतियों की

सूची में शू को 20वें स्थान पर रखा गया है, जो कि जैक मा से एक स्थान ऊपर हैं और हुआटेंग से दो स्थान ऊपर हैं. रियल एस्टेट दिग्गज को फोर्ब्स द्वारा 2017 में चीन का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था.

चीन की सिक्युरीटीज जर्नल के मुताबिक, हालांकि 2018 में उनकी दौलत थोड़ी घटी है. लेकिन एवरग्रीन के शेयरों में आई तेजी ने उन्हें दुबारा चीन के अमीरों की सूची में शीर्ष पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पिछले महीने से कंपनी के शेयरों में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है. इस सूची में शामिल होनेवाली पहली महिला यांग हुईयान है, जो प्रॉपर्टी डेवलपर है और उनकी संपत्ति 18.2 अरब डॉलर है. चीन के सबसे कम उम्र के अरबपति झांग यिमिंग (34) बाइटडांस के संस्थापक हैं. बाइटडांस एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने लोकप्रिय एप डॉयिन (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकटोक नाम से प्रचलित) विकसित किया है. झांग की संपत्ति अनुमानित 68 लाख डॉलर है.

चीन और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए हो सकती है बातचीत

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन और अमेरिका के वार्ताकारों ने मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत कर व्यापार वार्ता की समयसारिणी को लेकर चर्चा की। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी चिनफिंग के बीच व्यापार तनाव को विराम देने पर सहमति बनने के करीब 10 दिन बाद चीन के उप प्रधानमंत्री लियू ही ने अमेरिका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटाइजर ने बातचीत की। दोनों पक्षों ने समझौते पर पहुंचने के लिए 90 दिन की समयसीमा तय की है, लेकिन अगले दौर की बातचीत के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लियू और अमेरिकी मंत्रियों ने अगले दौर की बातचीत के लिए समयसारिणी पर चर्चा की और साथ ही आम सहमति को अपनाने की बात कही।

पाकिस्तान और चीन सीपीईसी नेट व्यापक बनाने के लिए सहमत हैं

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान ने सोमवार को चीन को आश्वस्त किया कि अरबों डॉलर की सीपीईसी 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' है और दोनों देशों के शीर्ष राजनयिक इन विकास परियोजनाओं का नये क्षेत्रों तक विस्तार करने पर सहमत हुए। दोनों सहयोगी देशों के बीच राजनीतिक संवाद के पहले दौर के दौरान पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ ने यात्रा पर आये चीन के उपविदेश मंत्री कोंग शुआनयू से कहा कि पाकिस्तान सीपीईसी परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए कटिबद्ध है। 60 अरब डॉलर का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) चीन में संसाधनों से समृद्ध मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह से सड़क, रेलवे और ऊर्जा परियोजनाओं से जोड़ने वाला योजनाबद्ध नेटवर्क है। सीपीईसी 2015 में शुरू हुई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ''दोनों पक्षों ने वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का निश्चय किया और सीपीईसी को पाकिस्तान के नेतृत्व की दृष्टि के अनुरुप सहयोग के नये क्षेत्रों तक ले जाने पर सहमति जतायी।'' दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे पर समग्र चर्चा की। कोंग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से भी भेंट की जिन्होंने पाकिस्तान चीन द्विपक्षीय वार्ता के सफल समापन पर चीन को बधाई दी।

इनकी फैन हैं विद्या बालन, मिलने के लिए किया ये काम

नई दिल्ली (एजेंसी)।

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर फोटो शेयरिंग वेबसाइट इंटाग्राम पर शेयर की है। इस तस्वीर के बारे में काफी बातें की जा रही हैं। इसकी बड़ी खास वजह भी है। यह तस्वीर अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रहीं हिलेरी क्लिंटन के साथ है। इसमें विद्या के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी हैं। विद्या ने यह तस्वीर हाल ही में संपन्न हुई मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की प्री वेडिंग संगीत फंक्शन में ली है। हिलेरी इस समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई थीं। विद्या ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने हिलेरी से उनका परिचय कराया। तस्वीर के कैप्शन में विद्या ने लिखा, जीवन में पहली बार मैंने किसी ने खुद का परिचय कराने के लिए कहा। शुक्रिया स्मृति ईरानी, ऐसा करने के लिए। मुझे हिलेरी क्लिंटन बहुत पसंद हैं। एक ऐसी महिला जिसने हर माहौल को समान रूप से झेला है और जो कभी हार नहीं मानतीं। मुझे बहुत उम्मीदें थीं जब वह अमेरिका की राष्ट्रपति पद की दावेदार थीं, और बहुत दुख हुआ जब वह नाकाम रहीं। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति सिद्धार्थ का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अमेरिकी राजनीति से उन्हें अवगत कराया और इस मुलाकात के लिए प्रेरित भी किया। ईशा अंबानी के प्री-वेडिंग इवेंट्स 8 और 9 दिसंबर को तय किए गए थे। अंबानी ने सभी मेहमानों के लिए चार्टेड फ्लाइट्स बुक करवाईं। शहर के सभी 5 स्टार होटल पूरी तरह बुक थे क्योंकि वे अंबानी और पीरामल को सेवाएं दे रहे थे। इतना

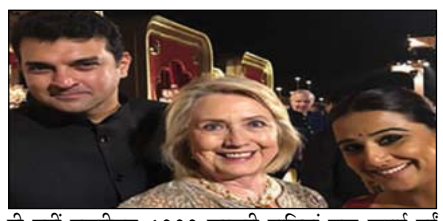

ही नहीं तकरीबन 1000 लग्जरी गाड़ियां बुक कराई गईं जो उदयपुर एयरपोर्ट से मेहमानों को लाने ले जाने का काम कर रही थीं।

107 साल की उम्र में भी रिटायर होने को तैयार नहीं दुनिया का सबसे उम्रदराज बार्बर

न्यू यॉर्क (एजेंसी)।

आप कहेंगे कि इस उम्र में लोगों की याद्दाश्त और सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। शरीर की ताकत खत्म बहुत कम हो जाती है और व्यक्ति अपने जरूरी काम करने में भी असमर्थ हो जाता है। मगर इसके बावजूद अमेरिका का यह हेयर ड्रेसर 107 साल की उम्र में भी रिटायर होने को तैयार नहीं है।

खास बात यह है कि अपने कस्टमर को सेवाएं देने के लिए इस उम्र में भी यह बार्बर दोपहर 12 से रात 8 बजे तक काम करता है। दुनिया के सबसे अधिक उम्र के बार्बर काम से रिटायर नहीं होना चाहते। इनका नाम एंथनी मैनसिनेली है। एंथनी सप्ताह के पांच दिन काम करते हैं। वह करीब 100 साल से बार्बर शॉप पर काम कर रहे हैं। 2007 में वह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले चुके एंथनी का कहना है कि वह काम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्हें घर बैठने पर बोरियत महसूस होती है।

1911 में जन्मे एंथनी मूल रूप से इटली के रहने वाले हैं लेकिन जब 8 साल के थे तो उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर की मानें तो एंथनी इस उम्र में भी बाल उसी कुशलता से काटते हैं जैसे जवानी में करते थे। कहा जाता है कि वे पिछले 96 साल से हेयर कटिंग कर रहे हैं। एंथनीदुनिया के सबसे बुजुर्ग हेयर ड्रेसर हैं। एंथनी ने हर उम्र के लोगों के बाल काटे हैं और उनके कस्टमर में उनका 81 साल का बेटा बॉब भी शामिल है।

एंथनी का कहना है कि वह अब भी काफी काम कर सकते हैं। घर पर रह कर वह बोर हो जाते हैं। अब भी वह हफ्ते में 5 दिन अपने सैलून में 8 घंटे तक काम करते हैं।

अपनी लंबी उम्र का राज बताने को तो वह तैयार नहीं हैं, मगर वह ये जरूर महसूस करते हैं कि अपने काम से प्यार करना ही शायद उन्हें जवान रखे हुए है। वह बताते हैं कि उनकी शादी 69 साल पहले हुई थी और 14 साल पहले एंथनी की पत्नी की मौत हो गई थी। वह उन्हें बहुत मिस करते हैं।

गिनीज बुक में नाम दर्ज होने के बाद से ही कई मशहूर हस्तियां उनकी प्रशंसक बन गई थीं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा और न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रू कुओमो भी शामिल हैं।

एंथनी का स्टेट बार्बर लाइसेंस 31 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रहा है पर एंथनी इसे जल्दी ही रिन्यू कराने की सोच रहे हैं। उनके एक ग्राहकों का भी कहना है कि इस उम्र में भी एंथनी का काम शानदार है, और उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है।

खरबों डॉलर रिश्वत में दिए गए, हर साल भ्रष्टाचार के जरिए चुराए गए: संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि प्रति वर्ष भ्रष्टाचार के जरिए खरबों डॉलर की चोरी होती है अथवा यह राशि रिश्वत के रूप में दी जाती है. यह राशि वैश्विक जीडीपी के पांच प्रतिशत से अधिक है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस पर भ्रष्टाचार को संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों पर प्रहार बताया. हर साल नौ दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है.

गुतारेस ने कहा, ''भ्रष्टाचार स्कूलों, अस्पतालों तथा समाज की अन्य अहम सेवाओं पर प्रहार करता है. विदेशी निवेश को विमुख करता है और देश को प्राकृतिक संसाधनों से विहीन करता है.'' प्रति वर्ष एक खरब डॉलर रिश्वत के रूप में दिए जाते हैं वहीं अन्य 2.6 खबर डॉलर की चोरी होती है. यह सब भ्रष्टाचार के चलते होता है.

संयुक्त राष्ट्र का यह बयान कई मायनों में अहम है क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिससे कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं और यह विकास की राह में भी बड़ा रोड़ा है.

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी बढत से कांग्रेसियों में खुशी की लहर

शहर में जगह-जगह फोडे गए पटाखे

ढोल नगाड़ों की धून पर नाचते दिखे कांग्रेसी

सूरत। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। जिसमें कांग्रेस ने अप्रत्याशित बढत हासिल की है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान मणिपुर तथा तेलंगाना में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने भारी उत्साह देखने को मिला। जिसका असर सूरत मे ंभी दिखा। कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने जीत की इस खुशी मे ंपटाखे फोडे तथा ढोल नागाड़े की थाप पर नाचते हुए नजर आए। पिछले कई वर्षों से सत्ता से दूर रहने वाले कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं मे ंअजब की खुशी थी। इस मौके पर कार्यकर्त्ताओं ने एक दूसरे को मीठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। खासकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है।

डी आर एम ने किया सूरत, उधना रेलवे का निरीक्षण

सूरत। मुंबई डिविजन के प्रभारी डी आर एम मुकुल जैन ने मंगलवार को सूरत तथा उधना रेलवे स्टेशन के कार्यों की जानकारी मिलते ही दोनों स्टेशनों पर पहले से ही तैयारी पूर्ण कर ली गई थी। इस बीच मुकुल जैन ने सूरत तथा उधना के कई अधिकारियों से बातचीत की सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मंगलवार की सुबह 6.30 बजे लोकल ट्रेन से डी आर एम मुकुल जैन सूरत पहुंचे दोपहर बाद उधना रेलवे स्टेशन के आस पास चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने गए। जहां अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार डी आर एम ने पिछले एक महीने में यात्रियों को मिली सुविधाओं तथा उनको हुई परेशानियों पर चर्चा की। विदित हो की सूरत रेलवे स्टेशन दक्षिण गुजरात का सबसे ज्यादा आमदनी कराने वाला रेलवे स्टेशन है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की घोषणा पिछले सरकारों द्वारा भी किया जा चुका है। परन्तु इसे अब तक तस्वीर नहीं बदली है। सूरत में यात्रियों की सुविधा के स्वचालित सीढिया लगाई गई। परन्तु उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही वह बांद हो गई। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई। परन्तु इस लिफ्ट का प्रयोग केवल वी.आर.पी के लोग ही कर पाते है। ज्यादातर समय लिफ्ट बंद ही रहता है। उधना में लगे लिफ्ट की चाभी कुलियों के पास रहती है। इन स्टेशनों पर विकलांग यात्रियों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। परन्तु ज्यादातर मामलों में बिना कुलियों को कीमत चुकाए लिफ्ट नहीं मिलता। सूरत रेलवे स्टेशन तथा उधना में वरिष्ठ नागरियों को स्टेशन से बाहर तक ले जाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। परन्तु इन ई रिक्शा का इस्तेमाल ज्यादातर सुविधा सम्पन्न लोगों ही ले पाते है। जिस पर बारीकी से निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

आसिफ गांडा सहित 21 पकड़े गए

बेगमपुरा में जुए के अड्डे पर छापा

सूरत। शहर के बेगमपुरा स्थित तुलसी फलिया के तिलक मैदान में चल रहे आसिफ गांडा के जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापामार कर 21 जुआरियों को पकड़ लिया।

महिधरपुरा पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि बेगमपुरा में आसिफ गांडा जुए का अड्डा चला रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सूचित जगह पर छापा मारा। छापे के दौरान 19 मोबाईल फोन, कोइन्स, 6 वाहन तथा नगदी मिलाकर 14.19 लाख का मुद्दा माल जप्त कर लिया। पुलिस ने जुआ खेल रहे आसिफ गांडा, रोहित सूर्यवंशी, हिरेन चोवटिया, अरुण शाह, कासिम शाह, गुलाम शबीर, रसिक पटेल, कांति भाई सवाणी, राकेश मराठी, अल्पेश पटेल नीतिन पटेल, विनोद मनोहर, मोहम्मद इमरान, संजय काशीनाथ, इकबाल कासम, असफाक खाटकी, संजय मराठी, सुभाष जादव, राजूमंगा, नजीक बस्तर, मुस्ताक इब्राहिम, दिलीप नायके तथा बहादुर राठौड़ की धरपकड़ कर उनके कब्जे से 1,91,799 रुपये का मोबाईल फोन, टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर मिलाकर कुल 6 वाहनों को जप्त किया। जिसकी कुल कीमत 14,19,700 बताई जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस कमिश्नर ने शहर में चल रहे जुए तथा शराब के अड्डे पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिसके तहत आए दिन पुलिस छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। विदित हो कि शहर में चल रहे अवैध धन्धों की वजह से शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। जुए तथा दारू के अड्डे चलाने वाले माफिया ज्यादातर कालेज के बच्चे फंसाते है तथा उनकी मासूमियत का फायदा उठाकर अपने कारोबार को बढाते है। ऐसा नहीं है कि स्थानीय पुलिस को चल रहे इस गौरखधन्धे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय पुलिस की रहमोकरम पर ही इस तरह के धन्धे फल फूल रहे है। ऐसे में जरुरत है कि पहले उन पुलिस वालो की भूमिका की जांच की जाए जिनके सह पर इस तरह के कारोबार को बढावा मिल रहा है।

सूरत शहर में फल फूल रहा अवैध जमीन का धन्धा

73एए, रिजर्वेशन, मार्जिन तथा सरकारी जमीनों को धड्डले से हो रहा सौदा

सूरत। देश के कोन-कोने से सूरत में अपनी आजीविका कमाने आए श्रमजीवियों को खुद का प्लाट दिलाने का झासा देकर उनकी पसीने की गाढी कमाई को लूटने का धन्धा सूरत शहर में इन दिनों खूब फल फूल रहा है। ये माफिया दलालों के माध्यम से 73 एए यानि वह जमीन जिसे सरकार ने अनुसूचित जाति को पट्टे पर दिया है को भी फर्जी कागजात के जरिए लोगों को बेचा जा रहा है। इस तरह का कारोबार ज्यादातर उन इलाकों में हो रहा है जहां श्रमजीवी रहते है। भू-माफिया ज्यादातर उन गरीबों को अपना शिकार बनाते है जो पढे लिखे नहीं है अथवा बहुत कम पढे लिखे है। इन गरीबों को उन जमीनों को बेचा जाता है जो किसी सोसायटी की मार्जिन की जगह है अथवा वह जमीन सराकी काम काज के लिए रजिर्वेशन में रखी गई है। इस काम में भूमाफिया को स्थानीय नेताओं का सह प्राप्त रहता है। ग्राम पंचायत में आने वाली इस तरह की जमीनों का सौदा सरपंच तथा तलाटी की मिली भगत से खूल चल रहा है। सूडा के क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीनों का सौदा सूडा के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की मैहरबानी से चल रहा है। अवैध जमीन की हैराफेरी का शिकार हुआ गरीब जब न्याय के लिए पुलिस थाने पहुंचता है तो पुलिस वाले यह कहकर उसे वहां से भगा देते है कि तुमने जमीन खीदते वक्त इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की। कई मामलों में पुलिस शिकायत दर्ज भी करती है तो आरोपी से सांठगाठ कर फरीयादी से समझौता करा देती है। ऐसे में गरीब व असहाय लोग अपनी किस्मत को कोसकर रह जाते है। कई मामले तो पुलिस तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती जब तक आरोपी वहा से फरार नहीं हो जाता ऐसे में पीडित को कहीं से भी न्याय नहीं मिलता और अन्त में वह हाथ मलकर रह जाता है।

इलेक्ट्रानिक उपकरणों की खरीदी के बाद भुगतान न करने पर पुलिस फरीयाद

सूरत। शहर के वराछा क्षेत्र स्थित धर्मा इलेक्ट्रानिकस नामक दुकान से 91000 रुपये का माल खीदने के बाद भुगतान न करने पर पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है।

वराछा पुलिस से मिली जानकारी अनुसार वराछा के गायत्री नगर के पास धर्मा इलेक्ट्रानिक्स नामक दुकान के मालिक पंकजभाई मधुभाई समोलिया ने आरोपी रोहन खन्ना निवासी श्रेनिक रेसीडेंसी, वेसू के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दिए शिकायत में यह कहा गया है कि आरोपी ने उसकी दुकान से 91000 रुपये का सामान खरीद कर बिना भुगतान किए मामल लेकर चला गया तथा भुगतान की राशि बाद में देने को कहा। परन्तु आरोपी अब भुगतान करने से मना कर रहा है। वराछा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। गौरतलब बै कि मंदी के इस माहौल में जहा दुकानदार एक एक ग्राहक के लिए टकटकी लगाए बैठा है वहीं कुछ ठग किस्म के लोग दुकानदार को चूना लगाने से भी नहीं चुकते जो अत्यंत ही दुभार्गयपूर्ण तथा शर्मनाक घटना है।

झपटमारों ने महिला के गले से चेन छीनी

सूरत। उधना के लक्ष्मीनारायण मंदिर के सामने से जा रही महिला के गले से सोने की चेन छीनकर झपटमार फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार दो अज्ञात बाईक सवारों ने इस घटना को अन्जाम दिया है। पुलिस ने महिला के शिकायत पर झपटमारी का मामला दर्ज कर लिया है। उधना पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पांडेसरा के दक्षेश्वर मंदिर के पास आकाश भूमि में रहने वाली सीमाबेन रामचन्द्र शर्मा उधना, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास से जा रही थी तभी पीछे से आए दो बाईक सवारों ने उनके लगे से सोने का चेन झपट लिया। लगभग 25000 रुपये कीमत का चेन लेकर झपटमार वहां से फरार हो गए। उधना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिलाओं के गले से चेन झपटने की घटना आए दिन बढती जा रही है।

सीमाडा में पाइप लाईन डालने का विरोध

आयुक्त ने किया मौके पर दौरा

सूरत। शहर के पूणा-सीमाडा क्षेत्र मे ंटी.पी. रोड पर पानी का पाईप लाईन डालने का स्थानीय वासियों द्वारा विरोध किया जाने के बाद मनपा आयुक्त ने स्थल पर पहंच कर मौके का मुआयना किया। प्राप्त जानकारी अनुसार कांग्रेस के पार्षद नीलेश कुंभाणी, विजय पानसूरिया, डी.पी वेकरिया सहित स्थानीय लोगों द्वारा मौर्चा निकाल कर पाईप लाईन न डालने का आवेदन पत्र दिया गया। मनपा कमिश्नर ने मौके पर मुआयना करने के बाद 10 मीटर चौडी सड़क पर पानी की लाईन डालने की जगह 30 मीटर की चौडाई वाले सड़क पर पाईप लाईन डालने का आदेश दिया। साथ ही पाईप लाईन के कारण प्रभावित होने वाले को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया। मनपा कमिश्नर एम. थन्नारासन के इस कदम का स्थानीय निवासियों ने स्वागत किया। विदित हो कि कई बार मनपा के अधिकारियों बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से टी.पी स्कीम में ड्रेनेज तथा पानी की पाईप लाईन के लिए ऐसे जगहों का प्रयोग किया जाता है जिससे गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों का ही नुकसान है बिल्डर का नहीं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)